of the Department of Company Affairs regarding the monitoring of borrowings by companies from the public.

Companies borrowing through deposits from the public are governed by the provisions of Section 58A of Companies Act, 1956. While borrowing, companies are required to comply with the provisions of Sections 292/293 of the Companies Act, 1956. During 1994 the Company Law Board has received applications against 125 companies in respect of non-repayment of deposits and/or interest due thereon.

During the years 1992-93 and 1993-94, 51 prosecutions under section 58A(10) and 82 other prosecutions under section 58A have been filed against Companies.

Fixed Deposits are normally used by companies for meeting working capital requirements.

**Enquiry into Bomb Blasts at Jammu**

*72. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have ordered an enquiry into the triple bomb blasts in Jammu on the Republic Day this year;

(b) if so, what are the findings of the enquiry; and

(c) the details of the follow-up action in these cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) to (c) The CBI has been entrusted with the investigation of the case. The report and findings of the investigation have not been received. In the meanwhile, a number of administrative measures have been taken to tighten the security arrangements.

**इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित किया जाना**

*73. **श्री राम जेठमलानी :**
**श्रीमती सुषमा स्वराज :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक नई योजना के तहत देश में लघु उद्योगों के लिये बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु संपूर्ण देश में 50 इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में कितने-कितने इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है तथा इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी योजना के समान देश में गत कुछ वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास केन्द्र (इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर) स्थापित करने की योजना लागू की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना के तहत कुल कितने केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था तथा मार्च, 1994 के अन्त तक वास्तव में कुल कितने केन्द्र स्थापित किये जा सके थे और नई तथा पुरानी योजना में क्या भिन्नतायें हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम)** : (क) जी, हां। सरकार ने लघु उद्योगों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये देश के ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों हेतु लगभग 50 स्वीकृत आधारभूत सुविधा विकास केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है ।

(ख) इस योजना के तहत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पात्र तथा जीव्यक्षम प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा । अब